HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 183 GIVEN ON 10TH MARCH, 2010 REGARDING 'MIGRATION OF LABOURERS'

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar): Sir, I raise a discussion on points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 10th March, 2010, to Starred Question No. 183 regarding 'Migration of Labourers'.

महोदय, पिछली बार सदन में एक प्रश्न आया था और उसमें माइग्रेशन के सवाल पर माननीय मंत्री जी का उत्तर आया था। हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि इस विषय में जो आंकड़े दिए गए थे, उस पूरे पत्रक में यह बतलाया गया था कि किस प्रकार से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। जो नियम लागू हुआ है, उसके तहत जाने वाले हर एक मजदूर या माइग्रेंट को रजिस्टर्ड किया जाना है। उस नियम के तहत उस व्यक्ति को जो भी दिया जाना है, उसके लिए सरकार ने पूरा प्रावधान किया है, लेकिन हम लोगों ने उस आंकड़े को देखा और जब उस आंकड़े का अध्ययन किया गया तो पूरे सदन में एक प्रकार से हंगामा हो गया कि आखिर ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? इसमें एक स्थान पर दिखाया गया था कि महाराष्ट्र के 2 करोड़ लोग महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं। एक स्थान पर यह दिखाया गया था कि बिहार में 70 प्रतिशत लोग बाहर से आकर काम करते हैं। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश के बारे में यह दिखाया गया था कि आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लोग आकर काम करते हैं। हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया। हम लोगों ने महाराष्ट्र में निरंतर यह देखा है कि मुम्बई शहर में लोग बार-बार इस बात को उठाते हैं कि साहब, बाहरी लोगों के आने से मुम्बई शहर भर गया है। इसके कारण वहां आपसी राजनीति होती है, लोगों में विरोध होता है, मारपीट होता है और देश में संकट पैदा होता है। यदि यह बात सच है कि मुम्बई या महाराष्ट्र से 2 करोड़ लोग बाकी राज्यों में जाते हैं तो मैं समझता हूं कि देश में यह एक अच्छी परम्परा है कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएं। जहां संभावनाएं हों, वहां जाकर वे काम कर सकें और उस राज्य की प्रगति में अपनी हिस्सेदारी देकर उस राज्य के काम में अपने हाथ बंटा सकें। यह तो अच्छी बात है।

(**श्री उपसभापति** पीठासीन हुए)

उसी तर्क के आधार पर हमने पूछा था कि सही तथ्य क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने उस पर जवाब दिया था कि इसमें तर्क यह है कि लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं। अब यह समझना बड़ा कठिन है। अगर मैं बिहार से आता हूं और लोग कहें कि बिहार में 70 लाख लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो अगर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं तो जो व्यवस्था है, उसमें आप आंकड़े कैसे रखते हैं? आपकी जो प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत कैसे आप आंकड़े एकत्रित करके हमें देते हैं? हम लोगों ने मूल रूप से यह विषय उठाया था। चूंकि माननीय मंत्री जी की तरफ से इस पर जवाब आना है, उनकी तरफ से सफाई आनी है तो मूल रूप से हम यह जानना चाहेंगे। यह पूरी सूची जो आपके द्वारा दी गई है, मैंने बड़ी कठिनाई से इस सूची को पुनः प्राप्त किया है। इसमें विदेशों से आने वाले लोगों की भी चर्चा की गई है।

इससे पहले कि आप अपनी सफाई दें कि कितने लोग किस राज्य में गये हैं, यह महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में इस समस्या का एक बार निदान करना है। क्योंकि यह देश हम सब लोगों का है और यह इतना खूबसूरत देश है कि हम पूर्वोत्तर में भी जाकर बस सकते हैं। हां, यह दूसरी बात है कि इस देश में एक ऐसा भाग है, जहां हम जाकर नहीं बस सकते। वह कश्मीर का इलाका है, जहां से लाखों को निकाल कर दिल्ली भेजा गया और वे देश के कोने-कोने में गये। उन्हें मारने की धमकी दी गई, उन्हें मारा-पीटा गया और उन्हें आतंकवादियों की गोली का निशाना बनाया गया। सरकार उस बारे में औसतन कुछ कहना नहीं चाहती है और कांग्रेस की सरकार तो कतई कुछ नहीं कहना चाहती है। माननीय मंत्री जी बतलाएं कि कश्मीर के लोगों को जो बाहर आकर मजबूरी में बसना पड़ा, उस विषय पर सरकार का क्या मंतव्य है? उन्हें आप किस श्रेणी में मानते हैं? अगर वे मजबूरी में आकर बाहर बसे तो क्या आप उन्हें माइग्रेट कैटगरी में मानते हैं?

यदि आप उनको migrant category में मानते हैं, तो उनकी सूची कहां है? वे देश के किस-किस कोने में जाकर बसे हैं, उनके आर्थिक और माली हालात कैसे हैं, इन सभी विषयों पर आप यदि हमें जानकारी देंगे, तो हमें प्रसन्नता होगी। इसके साथ ही इसी सवाल में विदेशों से आने वाले लोगों को परमिट देने की बात है। कई बार हमने RTI के माध्यम से तथा दूसरे माध्यमों से यह जानने का प्रयास किया कि इस देश में कितने चीनी नागरिक आए? कई पत्रकार ने मुझसे पूछा, कई NGOs ने पूछा कि क्या भारत में भी चीनी मूल के लोग आकर बसे हैं? हमें आज तक सरकार की ओर से इस बात का जवाब नहीं मिला है। कई बार RTI डाला गया, अप्रवासी मंत्रालय से पूछा गया, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं मिली है कि देश में कितने चीनी मूल के नागरिक आकर बसे हैं, जिनके पास यहां रहने की permission नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि दार्जिलिंग का क्षेत्र, सिलिगुड़ी का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम बागडोगरा से पार करते हैं, बीच में बिहार का हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है, आगे जाकर सिक्किम का हिस्सा है और फिर तिब्बत की सीमा है। इस भाग में निरंतर घुसपैठ हो रही है और बड़ी संख्या में लोग बंगला देश से सीमा पार करके भारत के भीतर जा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार सरकार को यह बताने की कोशिश की है कि यह जो chicken neck है, आज पिछले 20 वर्षों में इस पूरे इलाके का demographic proflie बदल गया है, उस इलाके का जो स्वरूप है, वह बदल गया है। आज जो गोरखालैंड का सवाल बड़े पैमाने पर उठाया जाता है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is only for half-an-hour. There are three more Members to speak.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: I will just conclude with these three questions. ...*(Interruptions)*... Sir, it is very important. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is only half-an-hour. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRTAP RUDY: Sir, I am asking three basic questions. First, I have talked about the migrants whose numbers have been given to us. Second, I have talked about the Chinese who

have come into India, their settlement and their numbers. The third question which I am raising is the infiltration on the chicken-neck location between Bangladesh and India which needs a specific reference from the Minister. Sir, why I am telling this is because when the Minister starts answering, all these three points should come to me, otherwise, I will have to move for one more half-an-hour discussion. So, all these three questions need to be answered by the hon. Minister.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. In this particular issue, Sir, the Government is having the system of taking data on the basis of the companies which are recruiting from one particular State. If they are recruiting from Bihar, then they are indicating that number. Similarly, if they are recruiting in Maharashtra, they are giving the number of those people who are being recruited for those companies. That data only is available with the Government at present. When we raised the question, we wanted to know whether the private companies and other companies are following the laws and they are fulfilling the legal principle and getting permission which is in the record. But there are companies which are violating the rules and they are not reporting to the concerned Department how many people they are recruiting from a particular State and how many people are living in the State during that period of working in that company. I would like to know whether there is any proposal from the Government to find out the real number of the migrant labour from one State to another and whether the principle of protecting their interests, the labour interest is also followed properly. That is the question which we raised, Sir.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Thank you, Sir. Shri Rudyji is talking about the Census report which is also important to know, but more important is how to protect the interests of the workers. The Census report or any other statistics in this country cannot be taken as correct because there is always a difference between a sample survey, a Government report, and an NGO report, That is not important. The important point is how best we can protect the interests of the migrant labour in this country. You have an instrument called the Industrial Migrant Labour Act. Now we have to examine whether this Act is adequate to protect the interests of the migrant labour because they have no house, no minimum wages, and no protection. So, I do not want to take much

of your time. I would like to ask the Government whether it is prepared to see how best they can do it and how we can implement the Rashtriya Swasthya Bima Yojana in respect of migrant workers.

I would like to know whether Government has any plan to implement the recommendation of the tripartite group on migrant workers and the Migrant Labour Act which is also in force now. I am asking this because labour is a concurrent subject and the labourers are working in a particular State, though their State of origin is a different one. So, it is very difficult to implement the Migrant Labour Act in the State. I would like to know whether Government will consider - as workers are working in various States and it involves the interest of around 14-15 crores of workers - the implementation of Labour Act and whether it can be taken over by the Central Government and whether there can be an alternative arrangement between the sending States and the receiving States so that this could be well coordinated and they could get the benefit. Sir, an amendment to this Act is required, which may include a penal provision for violation of this Act and fraudulent acquisition of license more stringent; making it obligatory for the principal employer not to get any work executed through an unlicensed contractor; permitting third parties including trade unions to file claims and/or make complaints on behalf of aggrieved persons; permitting filling of claim cases in the State of recruitment/origin in addition to the place of work; disbursement of wages in the presence of workmen's representative; providing for the presence of a workman's representative at the time of payment of wages; to permit filling of workmen's compensation claim in the event of his death in the originating State of the workers; providing for summary trial by executive magistrates; permitting third parties to file complaints; the penal provisions for the violations of the Act should be made deterrent by increasing the amount of fine to a minimum of Rs. 10,000; inter-State migrant workman or his/her legal heir or registered trade unions may also be permitted to file complaints independently in the State to which the migrant workman belongs or in the State where he works; the Act should provide for summary trail of offences by executive magistrate in order to facilitate speedy disposal of cases; an independent in built mechanism for recovery of claims should be incorporated. As per the existing provisions a workman has to approach different quasi-judicial authorities for his claims constituted under different legislations. This results in inordinate delay in the settlement of claims and the workman is suffering. The licensing authority should be notified as recovery authority and may be empowered to conduct summary trial into the claim and issue orders for payment within 15 days from

the date of filling claim because the interstate migrant workman will have no place to stay and no earning after the work is over. In case of non-payment of the amount ordered to be paid by Recovery Authority provisions should be made for levying fine at the rate of Rs. 100 per day per worker. ...(**Time-bell rings**)... Sir, I have one more point. The migrant worker does not have a ration card. He is not getting the ration card. He has no voting right and he has no place of living. Even in the city of Delhi, 16 lakhs of migrant workers who are engaged in the Commonwealth Games sites and Metro Railways are suffering in front of us. Sir, I think it is a very serious issue. Government should take this seriously and amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1979 so that 15 crores of workers will get relief. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want an answer from the Minister, please complete it within the time allotted, because we cannot extend it for more than half-an-hour.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Okay, Sir. I will quickly seek my clarifications. There are two kinds of migrant labourers. Some of them migrate and settle down there. They are also considered as migrant labourers because while replying to a question earlier, the hon. Minister said that there were 14 crores of migrant labourers. Fourteen crores are not moving from one State to the other every year. They are as good as settled down people. As a result, we say that registration should be done. Registration should be done in the State wherefrom they are migrating. Registration should also be done in the State where they are being employed.

All these things are not happening. If these things happen, we do not need the record of 2001. Then, every year there should be a record. So, that is not happening. Unless concerned laws are implemented, it is very difficult. For example, lakhs of workers are coming from Rajasthan to Delhi for constructing big buildings. Sir, buildings are constructed here. But, these people are still living under pathetic conditions in *Jhuggi Jhonpris*. There is law in a number of countries that when such big buildings are made, contractor should also be obliged to make some kind of housing for workers, so that they can also live like human beings. So, will the hon. Minister make some amendments to the concerned rules? These rules were made, probably, two or three decades ago. Why don't you make some amendments? In the present situation, if the migrant workers settling there, they should be able to live like human beings. This is one thing. Sir, I will finish quickly. I will not take long time of the House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, late comers should speak less.

SHRI SANTOSH BAGROD1A: Sir, I would also say one thing. Somebody told me that Maharashtra should become the financial hub of the world. I will be happy if one of the places of my country becomes financial hub of the world. But, can we have a financial hub where the labourers from anywhere in our country cannot go? They are questioned whether they have come for work. We can have financial hub only if there is peace. When there is peace, only then the entire country can be developed and anybody can go and work there. If our own workers cannot go, how can the foreigners go and work there? So, we cannot have a financial hub in that kind of a situation. This has to be understood by all the political leaders in the country. Unless these things happen and labourers are not looked after well, let me make it clear, by the Central and the State Governments and the employers, the country will not progress.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the point is...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I have not completed. Mr. Rudy, you are the first one to speak. Please, let me complete.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the House must pass a resolution. Unless he becomes Minister, he will take away all the time.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: So, for the sake of the country's development, we need to strengthen the labour laws of this country. Thank you.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : सर, यह Migrant Labour Act बहुत पुराना हो चुका है और मेरे ख्याल में यह adequate भी नहीं है। उसमें माइग्रेंट लेबर कौन है, इसकी definition भी बहुत perfect नहीं है। इसकी बुनियादी वजह तो यह है कि जिस ढंग से 1947 में इस देश का पार्टिशन हुआ और उसके बाद बहुत पैमाने पर नकलआबादी हुई, उसने इस मसले को और पेचीदा बना दिया, लेकिन उसके बाद यह देखा जाता है कि जिन रियासतों में land reform हुए, वहां से बहुत ज्यादा माइग्रेंट लेबर नहीं जाते हैं। हम पश्चिमी बंगाल की ही मिसाल आपको दे सकते हैं। वहां left run government के ज़माने में 40 लाख बीघा ज़मीन बगैर वाले किसानों को बांटी गई। वह मुफ्त बांटी गई, ज़मीन बांटी गई, एक एक परिवार को पांच-पांच बीघा जमीन दी गई। यह जो 40 लाख बीघा जमीन बांटी गई इससे गांव के लोगों को गांव में ही काम मिल गया। अब वहां से गांव के लोग शहरों में नहीं आते हैं और कोलकाता शहर के जो लोग हैं, वे भी बहुत कम दूसरे राज्यों में जाते हैं। वे जाते ही नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े बहुत तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वे permanent settle हो जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। वे आना-जाना करते हैं। इसलिए अगर land reforms पर पूरे देश में कोई आंदोलन चलता, तो यह मसला बहुत हलका हो जाता, बहुत ज्यादा लोगों को अपने ही वतन में रहने-खाने की जगह मिल जाती है। नहीं तो देखिए, रोटी की तलाश में गरीब लोग मारे-मारे फिरते हैं। सर, जो भी हिंदुस्तानी है, एक तो उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह एक

जगह से किसी दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, वोटर बन सकता है। यह अधिकार तो मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन यह जितना कम हो, उतना ही अच्छा है। उसका एक ही उपाय है - land reforms पर ज़ोर देना। मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल ने जो रास्ता दिखाया है, वह रास्ता पूरे देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी माइग्रेंट लेबरर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग माइग्रेशन करके चले जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम, उनका विकास, उनकी रोज़ी-रोटी का सवाल, सोशल सिक्योरिटी, ये चीज़ें कैसे उन तक पहुंचाई जा सकती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए वे एक नया कानून बनाएं।

جناب محمد امین صاحب (پچھمی بنگال) : سر، یہ Migrant Labour Act بہت پرانا ہو چکا ہے اور میرے خیال میں یہ adequate بھی نہیں ہے اس میں مائیگرینٹ لیبر کون ہے، اس کی ڈیفنیشن بھی بہت پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جس ڈھنگ سے 1947 میں اس دیش کا پارٹیشن ہوا اور اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر نقل آبادی ہوئی، اس نے اس مسئلے کو اور پیچیدہ بنا دیا، لیکن اسکے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن ریاستوں میں لینڈ ریفارمس ہوئے، وہاں سے بہت زیادہ مائیگرینٹ لیبر نہیں جاتے ہیں۔ ہم پچھمی بنگال کی ہی مثال آپ کو دے سکتے ہیں۔ وہاں left run government کے زمانے میں 40 لاکھ بیگھہ زمین بغیر زمین والے کسانوں کو بانٹی گئی۔ وہ مفت بانٹی گئی، ایک-ایک پریوار کو پانچ-پانچ بیگھہ زمین دی گئی۔ یہ جو 40 لاکھ بیگھہ زمین بانٹی گئی، اس سے گاؤں کے لوگوں کو گاؤں میں ہی کام مل گیا۔ اب وہاں سے گاؤں کے لوگ شہروں میں نہیں آتے ہیں اور کولکاتہ شہرکے جو لوگ ہیں، وہ بھی بہت کم دوسرے راجیوں میں جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہی نہیں ہیں-ایسی بات نہیں ہے، تھوڑے بہت تو جاتے ہیں، لیکن وہاں جاکر وہ permanent settle ہو جاتے ہیں-ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ آنا-جانا کرتے ہیں۔ اس لئے اگر لینڈ ریفارمس پر پورے دیش میں کوئی آندولن چلتا، تو یہ مسئلہ بہت ہلکا ہو جاتا۔ بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ہی وطن میں رہنے-کھانے کی جگہ مل جاتی، نہیں تو دیکھئے، روٹی کی تلاش میں غریب لوگ مارے مارے پھرتے ہیں۔ سر، جو بھی ہندوستانی ہے، ایک تو اس کو یہ ادھیکار ملنا چاہئے کہ وہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پر جاکر رہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، ووٹر بن سکتا ہے۔ یہ ادھیکار تو ملنا چاہئے، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے، لیکن یہ جتنا کم ہو، اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کا ایک ہی اپائے ہے - لینڈ ریفارمس پر زور دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھمی بنگال نے جو راستہ دکھایا ہے، وہ راستہ پورے دیش کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ابھی مائیگرینٹ لیبرس کی جو پرابلمس ہیں، ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں منتری جی سے دوخواست کروں گا کہ جو لوگ مائیگریشن کرکے چلے جاتے ہیں، ان کی سیکورٹی کا

انتظام، ان کا وکاس، ان کی روزی روٹی کا سوال، سوشل سیکورٹی، یہ چیزیں کیسے ان تک پہنچائی جا سکتی ہیں، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ ایک نیا قانون بنائیں۔

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : महोदय, इस विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है, खासकर श्री राजीव प्रताप रूडी ने कुछ सवाल उठाए हैं। इस संबंध में श्री रामचन्द्र खूंटिआ, श्री संतोष बागड़ोदिया और डा. नाच्चीयप्पन जी ने अपने सजेशंस दिए हैं। उसके बाद अमीन साहब ने अपने विचार यहां पर रखे। महोदय, इस बात को मैंने बहुत ही गंभीरता से लिया क्योंकि उस दिन श्री राजीव प्रताप रूडी तथा डिप्टी लीडर श्री एस.एस. अहलुवालिया जी ने यहां पर इस सवाल को उठाया कि जो migrant workers हैं - चाहे वे मुम्बई में हों, बिहार में हों या आंध्र प्रदेश में हों - उनके संबंध में जो आंकड़े हमने दिए थे, वे आंकड़े सही नहीं हैं इसलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये आंकड़े बहुत ही confusing हैं, इसलिए हम इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो आंकड़े हमने दिए थे, उनके संबंध में शायद मैं उस दिन explain करने में या आपको convince करने में विफल हो गया, मैं आपको convince नहीं कर सका। उस दिन अगर आप convince होना भी चाहते तो शायद नहीं होते क्योंकि आप इसको चर्चा में लाने की बात भी कर रहे थे। यह बात आज भी सही है कि हमने उस दिन जो आंकड़े दिए थे, वे 2001 के सेंसस के आधार पर ही दिए थे। उस दिन सवाल यह उठा था कि ये आने वाले भी हैं और जाने वाले भी हैं, इसमें से कौन सा सही है, इसके संबंध में आप बताइए? मैं उस वक्त इस संबंध में बताने में विफल रहा और फिर आधे घंटे की चर्चा के लिए इसको रिकमेंड किया गया और आधे घंटे की चर्चा के लिए आज यह यहां पर आया है। महोदय, मैं सेंसस की जितनी भी मार्गदर्शक सूची है, यानी गाइडलाइन्स हैं, उनके तहत बहुत से आंकड़े लाया हूं। एक village से town को जो ट्रांसफर्स होते हैं, Inter-District ट्रांसफर्स होते हैं, Intra-State ट्रांसफर्स होते हैं या Inter-State ट्रांसफर्स होते हैं, इसकी पूरी सूची अगर आप चाहते हैं तो वह आंकड़े मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यह सही है कि जो आंकड़े हमने यहां पर पेश किए हैं, वे सारे आंकड़े सेंसस की रिपोर्ट के आधार पर और उनका जो टेबल बनता है तथा इसके अलावा जो गाइडलाइन्स उन्होंने अपनी किताब में दी हैं, उसी आधार पर हमने होम डिपार्टमेंट से आंकड़े लेकर यहां पर पेश किए थे। इस संबंध में मैं छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं ताकि यह क्लैरीफाई हो सके। I am very happy that the hon. Members have raised the issues concerning migrant workers who are the most vulnerable sections of the society. We fully endorse the concerns expressed in the House. They are poor, illiterate, exploited by the intermediatories. They do not have fixed place of work, proper accommodation at work place. They have excess working hours and get inadequate wages.

We all know that migration takes place within the district, outside the district, outside the State and outside the country. There are various reasons for migration like work and employment, business, education, marriage, etc. As per Census 2001, information on migration of a person is

collected along with his activity status. For the purpose of Census, a person is considered a migrant on the basis of his place of last residence. A person is categorized as worker if he has participated in any economically productive activity at any time during the reference period. Based on the activity and migration status, the persons are classified as migrant workers.

Migration is a natural phenomenon and right of every citizen. As per the Census of 2001, the number of migrant workers was around 14 crores, as tabulated in Table D-8 of the Census Report. This number includes all types of workers, male and female, who have migrated. However, all migration does not take place on account of seeking work elsewhere but consequent to the migration, such person can become a worker. The number of 14 crore includes not only those persons who have migrated for work but also those who migrated and subsequently sought work. For example, a family member of the worker does not migrate for work, but on arrival to the destination, he or she seeks work. The data is, accordingly, collected separately for those who migrate for work and for those who migrate and subsequently seek work. There are other sub-categories of migrant workers within this number. We can continue to debate these numbers. However, the real issue is not the number but the welfare of these workers. I, therefore, turn now to this aspect in the context of what happened in the past, what we are attempting to do now and the plans for the future.

In order to safeguard the economic and other interests of the migrant labourers, the Government had enacted the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. The Act applies to every establishment or contractors in which five or more inter-State migrant workmen are employed. I must confess that there are various problems being faced in the implementation of the Act. Recognizing the problems faced by migrant workers, the Government placed these issues for deliberation at the multilateral forum of Indian Labour Conference so as to generate a wider debate amongst all the stakeholders. The issues were discussed at length in the last Indian Labour Conference on 20th - 21st February, 2009 and based on its recommendations the Government set up a Tripartite Group consisting of workers' representatives, employers' representatives as well as those from the Government to consider various issues relating to this extremely vulnerable section of unorganized workers. The Tripartite Group submitted its recommendations on 31.3.2010.

This is what you all expected. We are already at it and we have already requested the Committee to submit a report. They have submitted a report and we are going to examine what is to be done. These recommendations will be placed before the next meeting of the Indian Labour

Conference. However, the Government has already initiated action with regard to some of the recommendations of the Tripartite Group. As you know...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, we need the protection of the House now. Sir, this was a simple question and the whole House is hearing. He is talking about everything. I just asked one simple question. Have two crore people migrated from Maharashtra? It was a simple question. He has said everything. He has said about the entire policy. But a simple question whether two crore people have migrated from Maharashtra was not answered. It is a simple question. Sir, we need your protection for seeking a simple answer from the Minister. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Answer that Question.

...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I will come to that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We don't have time. It is 5.30. This is not debate. Half-an-Hour Discussion has to be completed within half-an-hour. ...*(Interruptions)*... You just answer that. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: One minute, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, he has asked a specific question. You please answer that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, that is the hon. Member's question. The other Members have asked different questions. Therefore, I have to answer them also and I have also to answer Mr. Rudy's question. Sir, whatever figures I have given, I have said that we have got this figure of 14 crore from the Census and the State-wise figures, whether it is Jammu & Kashmir or whether it is Punjab, Chandigarh, Mumbai, Uttar Pradesh, etc. These are the migration figures for the States. ...*(Interruptions)*... 'Migration' means going from the original place to the place where they are residing during Census. ...*(Interruptions)*... Yes, that is the confusion. ...*(Interruptions)*...

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : आप अपने उत्तर को कह दीजिए कि वह सही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मुझे मालूम है। ...(**व्यवधान**)... जो कंफ्युजन हो रहा है। वहां पर ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : आपके उत्तर में दो करोड़ लिखा है। ...(**व्यवधान**)...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : सर, मंत्री जी मान लें कि गलत लिखा है, वह उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : उनका कहना है कि महाराष्ट्र की पापुलेशन दो करोड़ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैंने इसीलिए डेफिनेशन पढ़ी है। आप सुन लीजिए। The number of total migrant workers क्या है? It is 2,06,85,108. This consists of intra-districts, inter-districts within the State, inter-State and international figures. We have given this figure taking all of them together. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He confirms that figure. ...*(Interruptions)*... He confirms that figure. You may say it can't be, but he confirms that figure. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the migration takes place in Maharashtra within the State, within the districts, within the Panchayats and within the country. ...*(Interruptions)*... This is a question which the entire House must understand. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct. You have made your point and you again wanted a clarification. ...*(Interruptions)*... The Minister replied that that is the figure. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, we need a complete enquiry into the subject. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different question. ...*(Interruptions)*... खूंटिया जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, when 2 crore inter-migrants are there from Maharashtra, one crore in Madhya Pradesh, 70 lakhs in Bihar and 30 lakhs in Delhi, there is something wrong here. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is not wrong. It is village to town. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If I understood, it is intra-district, intra-state, all put together. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is furnished by the Home Department. It is not ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See even in discussion, if you want a ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, tell me the district in this country where this system or intra-district migration is noted down.

There are people from the Left; there are people from all political parties. When anyone makes this statement ...*(Interruptions)*... This is an absurd answer. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is talking about ...*(Interruptions)*... Mr. Rudy, Census is something else. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: He cannot take the Parliament for a ride. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I want only a minute. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I have to finish the half-an-hour discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, for his information, I would give only one clarification. Hon. Member, Rudy ji, if you look at page 92, instruction manual for filling up household scheduled ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to stop this. You may provide the required information to the hon. Member later. ...*(Interruptions)*... The half-an-hour discussion is over.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, can we have a statement by the Minister of State in the Ministry of External Affairs? We could have clarifications on that later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If all of you agree. ...*(Interruptions)*...

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Then we would like to seek clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When we take up clarifications on Ministry of External Affairs, these clarifications could be taken up along with that. ...*(Interruptions)*...